शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 46 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 4 – 11 नवम्बर 2024 मूल्य पांच रूपये

क्या नये गठन में एक व्यक्ति एक पद पर अमल हो पायेगा?

- जब सरकार मित्रों की है तो संगठन में मित्र कैसे बाहर रहेंगे?
- क्या नयी टीम स्पष्टीकरणों को स्पष्ट कर पायेगी?
- क्या नयी टीम व्यवस्था परिवर्तन को परिभाषित कर पायेगी?

शिमला/शैल। कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश की राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर तक सभी ईकाईयों को भंगकर दिया है। राजनीतिक हल्कों में इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में आये दो वर्ष होने जा रहे हैं। प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने प्रदेश विधानसभा के चुनावों से पहले संगठन की अध्यक्षता संभाली थी। बल्कि जब मण्डी से लोकसभा का उप चुनाव लड़ा था तब कुलदीप राठौर अध्यक्ष थे। प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में पार्टी विधानसभा चुनाव जीत कर सत्ता में आ गयी। परन्तु पार्टी की सरकार बनने के बाद लोकसभा की चारों सीटें हार गयी। राज्य सभा चुनाव के दौरान चुनाव हारने के साथ ही पार्टी के छः विधायक भी संगठन को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गये। इन विधायकों के पार्टी छोड़ने के कारण हुये विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस ने फिर से चालीस का आंकड़ा तो हासिल कर लिया लेकिन इसी चुनाव में लोकसभा की चारों सीटें हार जाने का सच हाईकमान को शायद अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। ऐसे में विश्लेषकों के लिये यह एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि आखिर हाईकमान को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। प्रतिभा सिंह निष्क्रिय पदाधिकारी को बाहर करने की बात अकसर करती रही है। अब हाईकमान ने प्रतिभा सिंह की बात मानकर संगठन को नये सिरे से गठन करने की सिफारिश मानकर क्या संदेश दिया है यह समझना आवश्यक हो जाता है।

यह एक स्थापित सच है कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिये संगठन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन सरकार बनने के बाद संगठन को साथ लेकर चलना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव सामूहिक नेतृत्व के नाम पर लड़ा था। विधानसभा चुनाव में संक्खू मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं थे। सुक्खू मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व की पसंद के कारण बने हैं। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद सबको साथ लेकर चलना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी। परन्तु मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रीमण्डल की शपथ के पहले मुख्य संसदीय सचिवों को शपथ दिलाना शायद पहला फैसला था जिस पर संगठन में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ था। जिस तरह की कानूनी स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण बन चुकी थी उसके परिदृश्य में यह नियुक्तियां कोई बड़ी राजनीतिक समझ का प्रदर्शन नहीं थी। बल्कि आज भी न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा बनी हुई है। विपक्ष का फिजूल खर्ची पर यह पहला हमला होता है। वितीय संकट में चल रहे प्रदेश में ऐसी नियुक्तियों की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे होने की चेतावनी इन नियुक्तियों से पहले ही दे दी गयी थी। फिर इन नियुक्तियों के बाद कैबिनेट रैंक में सलाहकारों और ओएसडी आदि की तैनाती ने स्थितियों को और गंभीर बना दिया। जब मंत्रिमण्डल का गठन हुआ तो उसमें कुछ पद खाली छोड़ दिये गये। खाली छोड़े गये पदों में से जब दो भरे गये तो उन्हें विभागों का आबंटन करने में ही आवश्यकता से अधिक देरी कर दी गयी। इस तरह राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनती चली गयी कि संगठन सरकार में तालमेल का अभाव स्वतः ही सार्वजनिक होने लग पड़ा। राज्यसभा चुनाव तक पहुंचते- पहुंचते स्थितियां प्रबंधन से बाहर हो गयी।

मुख्यमंत्री ने पदभार संभालते ही प्रदेश की हालत श्रीलंका जैसे होने की चेतावनी तो दे दी थी। लेकिन उससे निपटने के लिए कर्ज और कर लगाने का आसान रास्ता चुन लिया। यह रास्ता चुनने के कारण विधानसभा चुनावों में दी गारंटीयां पूरी करने में कठिनाई आना स्वभाविक था। इसके परिणाम स्वरूप हर गारंटी में पात्रता के राइटर लगाने पड़ गये। राइटर लगाने का अघोषित कारण केन्द्र द्वारा आर्थिक सहयोग न मिलना प्रचारित किया गया। परन्तु इस प्रचार पर सुक्खू के कुछ मंत्रियों ने ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिये। भाजपा नेताओं ने केंद्रीय सहायता और सरकार द्वारा कर्ज लेने के आंकड़े जारी करने शुरू कर दिये। स्थितियां यहां तक उलझ गई कि प्रदेश की कठिन वितीय स्थिति का रिकॉर्ड विधानसभा के पटल पर रखते हुये मुख्यमंत्री को वेतन भत्ते निलंबित करने का फैसला पटल पर रखना पड़ गया। सरकार ने वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिये जिस तरह का करभार जनता पर बढ़ाना शुरू किया उन फैसलों पर सरकार जगहसाई का पात्र बन गयी। हर फैसले का स्पष्टीकरण जारी करने की बाध्यता बन गयी। अब जिस तरह से समोसा कांड और मुख्यमंत्री के फोटो प्रैस में जारी करने पर सरकार को पत्र लिखने पड़ गये हैं। उससे यह सीधे सन्देश गया कि शायद शीर्ष नौकरशाही पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है। फैसलों के स्पष्टीकरणों से भाजपा के आरोप स्वतः ही प्रमाणित होते जा रहे हैं।

ऐसी वस्तुस्थिति में संगठन की इकाईयां भंग करके नये सिरे से गठन करने की कवायद का कितना व्यवहारिक लाभ होगा इस पर चर्चाएं चल पड़ी है। क्योंकि सरकार पर एक आरोप मित्रों की सरकार होने का बड़े अरसे से लगना शुरू हो गया है। ऐसे में स्वभाविक है कि यह मित्र लोग संगठन में भी बड़ा हिस्सा चाहेंगे। जबकि इस समय संगठन में ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो अपनी ही सरकार से तीखे सवाल पूछने का साहस रखते हो। क्योंकि सरकार का सन्देश कार्यकर्ता के माध्यम से ही जनता तक जाता है और इस समय फैसलों के स्पष्टीकरण के अतिरिक्त जनता में ले जाने वाला कुछ नहीं है। सरकार की परफॉरमैन्स अपनी गारंटीयों के तराजू में ही बहुत पिछड़ी हुई है। गारंटी 18 से 60 वर्ष की हर महिला को पन्द्रह सौ देने की थी जो अब पात्रता के मानकों में ऐसी उलझ गयी है की आने वाले समय में सरकार की सबसे बड़ी असफलता बन जायेगी। यही स्थिति रोजगार के क्षेत्र में है। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि इस परिदृश्य में संगठन का पुनर्गठन किन आधारों पर होगा। क्योंकि यह सरकार जिस तरह की वस्तुस्थिति में उलझ चुकी है उससे बाहर निकल पाना आसान नहीं होगा। नये पदाधिकारी सरकार के फैसलों पर कैसे अपना पक्ष रख पायेंगे? क्योंकि वित्तीय संकट के लिये पिछली सरकार को कोसते हुए उसके खिलाफ कौन सी कारवाई शुरू की गयी है। इसका कोई जवाब इस सरकार के पास नहीं है। ऐसे में यह पुनर्गठन प्रदेश नेतृत्व से ज्यादा हाईकमान की कसौटी बन जायेगा।

राज्यपाल ने अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जिला शिमला के रामपुर बुशहर में चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल

भी उपस्थित थी।

राज्यपाल ने कहा कि सदियों से लवी मेले ने व्यापारिक मेले के रूप में अपनी पहचान कायम की है और वर्तमान में प्रदेश के सांस्कृतिक उत्सव के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि यह मेला प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है और हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष रामपुर में लोग व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेने के साथ-साथ परंपरा, एकता और सौहार्द की भावना को सुदृढ़ करते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि इस मेले का अपना ऐतिहासिक महत्त्व है और यह व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक समूह एक मंच पर देश की विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन कर अनेकता में एकता की भावना का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह मेला संस्कृतियों, विचारों और व्यापारिक गतिविधियों का संगम है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में रामपुर का वाणिज्य और सांस्कृतिक केंद्र बन कर उभर रहा है। यह मेला लोगों के लिए आर्थिकी सुदृढ़ करने के साथ-साथ सामाजिक सम्बधों को सुदृढ़ करता है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को संबल मिलता है और प्रदेश की संस्कृति का संवर्धन होता है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने माता भीमाकाली से प्रदेश के लोगों की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की और लवी मेले के सफल आयोजन के लिए आयोजकों के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि मेले में ऊनी वस्त्र, सूखे मेवे और अन्य पारंपरिक शिल्प कला का प्रदर्शन किया जाता है। यह मेला पारंपरिक कारीगरों, बुनकरों तथा किसानों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बेचने का सुनहरा अवसर उपलब्ध करवाता है। उन्होंने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से संस्कृतियों का विलय हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुंभ की तरह लवी मेला सांस्कृतिक पहचान कायम कर रहा है।

इससे पहले, राज्यपाल ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अन्य संगठनों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनियों का शुभारम्भ तथा अवलोकन किया।

उपायुक्त एवं अंतरराष्ट्रीय लवी मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष अनुपम कश्यप ने मेले के दौरान आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी भी दी।

राज्यपाल ने एनजेपीसी परियोजना स्थल का दौरा किया

शिमला/शैल। शिमला जिला के रामपुर में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 1500 मेगावाट क्षमता के नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना स्थल का दौरा किया। उनके साथ लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उपस्थित थीं।

राज्यपाल ने भूमिगत सुरंग और टरबाइन परिसर का भी दौरा किया, जहां परियोजना प्रमुख मनोज कुमार ने उन्हें परियोजना की अभियांत्रिकी से अवगत करवाया।

इसके उपरान्त, राज्यपाल को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से परियोजना की विभिन्न उपलब्धियों और अन्य गतिविधियों के बारे में भी अवगत करवाया।

महाप्रबंधक विद्युत विकास महाजन और पंकज चौधरी ने भी प्रस्तुतिकरण दिया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि एसजेवीएन ने देश को विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह लाभ अर्जित करने वाले कुछ प्रमुख संगठनों में से एक है और यह केंद्र सरकार की एक महत्त्वपूर्ण संपत्ति है। उन्होंने कहा कि नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है और परियोजना प्रबंधन द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विभिन्न गतिविधियां कार्यान्वित करना सराहनीय है।

राज्यपाल ने हार्ड कोटिंग चैंबर का भी दौरा किया।गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

राजभवन में मनाया गया 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस

शिमला/शैल। राजभवन में केंद्र शासित प्रदेशों सहित 15 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के सपने को साकार करते हुए यह आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल कार्यक्रम

में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले इन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

इस अवसर पर शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का प्राथमिक लक्ष्य राज्यों के बीच परस्पर संवाद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। साझेदारी के माध्यम से राज्यों को अपनी संस्कृति, पर्यटन, भाषा और शिक्षा के पहलुओं को एक-दूसरे के साथ साझा करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों, विशेषकर युवाओं को अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और राष्ट्रीय बंधन को मजबूत करने में मदद मिलती है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ व समन्वय बढ़ाती है और सम्मान को बढ़ावा देती है, जिससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है।

राज्यपाल ने कहा कि इन दिवसों को मनाने का उद्देश्य भाईचारे की भावना को बढ़ाना, अखंडता और प्रेम की भावना को मजबूत करना तथा राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के प्रयासों को याद करना है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह एकजुट, समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भारत के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है।

उन्होंने कहा कि इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें इस पहल की भावना को अपनाना चाहिए, यह समझते हुए कि अंत में, भारतीय के रूप में हमारी साझा पहचान सबसे महत्वपूर्ण है।

राज्यपाल ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस मनाने की प्रथा अन्य सभी राज्यों में भी शुरू की गई है, ताकि उनके इतिहास, संस्कृति और रीति-रिवाजों को बेहतर ढंग से जाना और समझा जा सके। उन्होंने कहा कि हम किसी भी राज्य, समुदाय, जाति या पंथ से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन हम पहले भारतीय हैं और समाज के सभी वर्गो को जागरूक करना व एकमत और स्नेह का संदेश फैलाना आवश्यक है।

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि इस तरह के मिलन समारोह एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। उन्होंने कहा कि हर राज्य की अलग-अलग वेशभूषा और संस्कृति है, लेकिन फिर भी हर भारतीय का दिल भारत के लिए धड़कता है। उन्होंने कहा कि आज हर व्यक्ति को समाज से जुड़े रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीयता हमारी पहचान है।

इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी मौजूद थीं।

राज्यपाल और लेडी गवर्नर ने 15 राज्यों के नागरिकों को सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख राज्यों के लोगों ने भाग लिया।

उन्होंने राज्यपाल के साथ बातचीत भी की और हिमाचल में अपने अनुभव साझा किए और अपने राज्यों की संस्कृति और रीति-रिवाजों के बारे में भी जानकारी दी।

कर्नाटक से संबंधित पूर्व पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि विविधता में एकता भारत की पहचान है और आज यह देखकर प्रसन्नता हुई कि केरल का एक व्यक्ति सियाचिन में भी देश की सेवा कर रहा है।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा तथा अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राष्ट्रीय सारस्वत सम्मान से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में नवाजे गये गौरव शर्मा

शिमला/शैल। राष्ट्रवादी विद्वानों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय सारस्वत परिषद के

तत्वाधान में 10, नवम्बर, 2024 को बीएचयू, वाराणसी में सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है। गौरव शर्मा (समाज सेवा क्षेत्र) जो कि नगर निगम शिमला के पूर्व पार्षद व भाजपा के युवा नेता है साथ में समाजिक गतिविधियों में सदैव तत्पर रहते हैं। गौरव शर्मा को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनोज दीक्षित तथा कार्यक्रम अध्यक्ष अखिल भारतीय गो सेवा प्रमुख संघ प्रचारक अजीत प्रसाद के हाथों सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वैदिक विज्ञान केन्द्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के व्याख्यान कक्ष में किया गया।

इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रें में सराहनीय कार्य करने वाले देश के 30 अग्रणी विभूतियों को सम्मानित किया गया। शिमला के ही शिक्षक पीयूष शर्मा को शिक्षा क्षेत्र में सारस्वत सम्मान दिया गया।

राज्यपाल ने नायब सूबेदार राकेश कुमार की शहादत पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र की छम्यार पंचायत के बरनोग गांव के रहने वाले नायब सूबेदार राकेश कुमार की शहादत पर शोक व्यक्त किया है।

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि राष्ट्र के लिए नायब सूबेदार राकेश कुमार का सर्वोच्च बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। वह युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।

उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शान्ति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। जिला सिरमौर में अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ददाहू में भगवान परशुराम की पालकी को कंधा देकर शोभायात्रा की अगुवाई की।

इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले और त्यौहार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। इस प्रकार के आयोजन स्थानीय लोगों को अपनी विशिष्ट लोक कला, संगीत, नृत्य और रीति-रिवाजों की अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करते हैं और भावी पीढ़ी प्रदेश की संस्कृति से रू-ब-रू होती है। उन्होंने कहा कि राज्य में मेले और त्यौहार पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होते हैं और देश-विदेश से भारी संख्या में पर्यटक इनमें भाग लेते हैं।

इसके उपरान्त, मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष वह अस्वस्थ होने के कारण मेले में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस वर्ष पहली बार मेले में आकर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। उन्होंने कहा कि मेले और उत्सव हमें धर्म के मार्ग पर चलने

के लिए प्रेरणा देते हैं।

एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि श्री रेणुका जी बांध का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। एफसीए क्लीयरेंस के कारण परियोजना लंबित है, लेकिन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम और माता श्री रेणुका जी मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेश में शांति व समृद्धि की कामना की। उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का भी शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर लगभग 300 महिलाओं द्वारा महानाटी भी प्रस्तुत की गई।

उप-मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सहकारिता विभाग

की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों के साथ विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की और सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं उनकी आधारभूत सरंचनाओं को विकसित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारी समितियों का पूर्णत: कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है। पहले चरण में लगभग 870 समितियों के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में हिमाचल पहला राज्य है, जिसने समितियों के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ता से कार्य कर रही है। इस दिशा में विभाग द्वारा अनेक पहल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने का महत्त्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने सहकारिता के क्षेत्र में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रदेश की अनेक सहकारी समितियां सराहनीय कार्य कर रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बैठक में सचिव सी पॉलरासु, रजिस्ट्रार डा. राज कृष्ण प्रूथी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नादौन मेरी कर्मभूमि, 20 साल से कर रहा हूं सेवा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के पुतड़ियाल में 'सरकार गांव के द्वार'

कार्यक्रम की अध्यक्षता की जहां 147 जन शिकायतें प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भी इस कार्यक्रम में अपनी पूरी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि जनता की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने पुतड़ियाल क्षेत्र के लिए कई विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने पुतड़ियाल विद्यालय के लिए नए भवन का निर्माण और पर्याप्त स्टाफ के साथ उप-स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लालू-धनियारा और पुतड़ियाल तलाई सड़क मार्ग के निर्माण लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पार्क और खेल मैदान विकसित करना भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिले के साथ-साथ प्रदेश भर में सड़कों को डबल लेन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बीच 75 लाख लोगों के उज्ज्वल भविष्य के लिए राज्य सरकार कठोर फैसले ले रही है। उन्होंने लोगों की भलाई और कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त बिजली, पानी और बस परिवहन के वायदे किए गए। उन्होंने कहा कि चुनावों से महज कुछ दिन पहले बिना किसी बजट प्रावधान के 900 संस्थानों को खोलने और अपग्रेड करने के फैसले लिए गए जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने लोगों को सुविधाएं देने के बजाय राजनीति की जिससे राज्य के संसाधनों को क्षति हुई। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नादौन मेरी कर्मभूमि है और उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय से यहां के लोगों की सेवा की है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार व्यक्त करते हुए कि काम के दम पर सभी का भरोसा जीतकर वे मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे पूरे समर्पण और लगन के साथ काम करते हुए लोगों की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

उन्होंने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के पांच लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।

केन्द्र से ईरान के सेब के आयात पर तुरंत रोक लगाने की मांग:राठौर

शिमला/शैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह देश की प्रमुख सेब आर्थिकी को तहस नहस करने में लगी है। उन्होंने कहा है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत देश में अफगानिस्तान के रास्ते अवैध रूप में ईरान का सेब देश लाया जाना बहुत ही चिंता की बात है। राठौर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर भारत मे विदेशी सेब के विपणन को बढ़वा दे रही है जिससे भाजपा को विदेशी फंड में लाभ मिल सकें। राठौर ने विदेश से आने वाले सेब के मामले को प्रदेश विधानसभा में भी उठाया था और इसके बाद प्रदेश सरकार ने इस बारे केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा था। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद कि हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों के हितों से कोई खिलवाड़ नही होने दिया जाएगा ईरान का सेब अवैध रूप से अफगानिस्तान के रास्ते भारत मे आना बहुत ही गम्भीर मामला है। इसके चलते कोल्ड स्टोरेज में रखवा गया देश के सेब की मांग कम होना बहुत ही चिंता की बात है।

राठौर ने केंद्र सरकार से ईरान के सेब के आयात व विपणन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल के सेब बागवानों के हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ सहन नही किया जा सकता।

पूर्व सरकार ने जनमंच कार्यक्रमों पर फूंके करोड़ों:संजय अवस्थी

शिमला/शैल। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा

सरकार ने जनमंच और स्थापना दिवस कार्यक्रम के नाम पर करोड़ों रुपये फूंक दिए। चुनाव जीतने के लिए पूर्व सरकार ने कर्मचारियों के लिए 10,600 करोड़ रुपये के संशोधित वेतन और महंगाई भत्ते की घोषणा तो की लेकिन एरियर का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का 10 हजार करोड़ वेतन और 600 करोड़ डीए के एरियर का भुगतान लंबित है।

मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि पूर्व सरकार ने महंगाई भत्ते की घोषणा की लेकिन इसका भुगतान नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार 15वें वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल प्रदेश की सही तरीके से पैरवी नहीं कर पायी जिसका खामियाजा हिमाचल भुगत रहा है।

संजय अवस्थी ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान धर्मशाला में हुई इन्वेस्टर्ज़ मीट में 19 करोड़ रुपये स्वाह कर दिए गए और 6 करोड़ रुपये की चपातियां डकार ली गयी। राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का किराया तक नहीं दिया गया। वित्त आयोग ने मंडी हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपये, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपये और शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपये देने का वायदा किया था लेकिन यह राशि भी जारी नहीं की गई। वित्त आयोग से प्रदेश को कुल 1420 करोड़ रुपये आज तक नहीं आया है। इसी तरह, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र बेचे गये।

उन्होंने कहा कि भाजपा कर्मचारी हितैषी होने का नाटक रचती है लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कर्मचारियों पर की गई अपनी टिप्पणियां याद रखनी चाहिए, जिन्होंने यहां तक कह दिया था कि कर्मचारियों को पैन्शन चाहिए तो नौकरी से त्याग पत्र देकर चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के सारे षडयंत्र विफल होने के बाद भाजपा नेता लोगों को बेबुनियाद मुद्दों पर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।

शिमला के होटल हॉलीडे होम में निदेशक मंडल की बैठक आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष आरएस बाली की अध्यक्षता में होटल हॉलीडे होम में निदेशक मंडल की बैठक अयोजित की गई। इस दौरान बैठक में कई महत्वपूर्व निर्णय लिए गए।

आरएस बाली ने कहा कि निगम की आय में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है और इस वर्ष भी आशातीत बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि निगम के होटलों में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलें, इसके लिए कई सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। होटलों की मरम्मत के साथ-साथ नया तकनीकी स्टाफ भतह करने का फैसला लिया गया ताकि पर्यटक अच्छे माहौल में रहने और जायकेदार व्यंजनों का लुत्फ उठा सकें। मनाली के अलावा कुछ होटलों में निगम क्लब हाऊस और आइस स्केटिंग रिंक की सुविधा भी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि पर्यटन निगम एक नया कार्यालय शिमला के होटल ह लीडे होम के साथ बनाया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम के होटलों में पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए एक कंपनी के साथ करार किया जा रहा है।

होटल के कमरे की बुकिंग होते ही कंपनी निगम को अग्रिम भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की सबसे बड़ी कंपनी के साथ यह करार किया जाएगा।

आरएस बाली ने कहा कि निगम ने सेवानिवत्त कर्मचारियों को 64 करोड़ रुपये की अदायगी की गई है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा घाटे में चल रहे होटलों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक पहल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि निगम ने होटलों को ए, बी, सी तीन वर्गों में बांटा है और इसी आधार पर होटलों को बेहतर बनाया जा रहा है।

आरएस बाली ने कहा कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरूण श्रीधर का हिमाचल पर्यटन क्षेत्र में लंबा अनुभव है। उनके आग्रह पर ही तरूण श्रीधर नि:शुल्क सेवाएं देने के लिए तैयार हुए हैं। उनका मार्गदर्शन निगम को ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा।

श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर मे विश्वास।
.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

एकाधिकार पर राहुल गांधी की चिंताएं और कुछ सवाल

पिछले एक दशक में जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली है तेईस सार्वजनिक उपक्रम पूरी तरह प्राइवेट सैक्टर के हवाले कर दिये गये हैं। विनिवेश योजना के तहत बैंकिंग, एलआईसी, रेलवे एयरपोर्ट में भी काफी हिस्सा प्राइवेट को देने की योजना है। विनिवेश के तहत कुछ प्राइवेट कंपनियां बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हैं। कुछ कंपनियों का करीब दस लाख करोड़ का एनपीए बट्टे खाते में डाल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में एक भी सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना नहीं की है। सार्वजनिक उपक्रमों को विनिवेश के तहत प्राइवेट सैक्टर के हवाले करने का रोजगार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस समय केन्द्र सरकार में करीब एक करोड़ पद खाली हैं। कंपनियों के एनपीए को बट्टे खाते में डालने से करीब दस लाख करोड़ की चपत सरकार को लगी है और इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। 2014 में जब डॉ. मनमोहन सिंह ने सत्ता छोड़ी और नरेन्द्र मोदी ने संभाली तब देश का कुल 55 लाख करोड़ का कर्ज था। जो अब 2024 में आरबीआई के मुताबिक 155 लाख करोड़ हो गया है। इस बढ़ते कर्ज के साथ ही जो लोग बैंकों को धोखा देकर विदेश भाग गये हैं उनमें से किसी को भी यह सरकार अभी तक वापस नहीं ला पायी है। इस सब का देश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक अरसे से चिन्ता व्यक्त करते आ रहे हैं। उनकी इस चिन्ता में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके साथ शामिल रहे हैं।

देश की आर्थिक स्थिति का यह गंभीर पक्ष है जिस पर एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी जब से इन एकाधिकार के प्रयासों में लगी कंपनियों के खिलाफ मुखर हुये हैं देश की जनता ने उनकी चिताओं को समझ कर कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष के पद तक पहुंचा दिया है। राहुल गांधी की चिंताएं जायज हैं और भविष्य के गंभीर प्रश्न हैं। क्योंकि एकाधिकार कहीं पर भी किसी का भी कालांतर में घातक ही सिद्ध होता है। बाजार में इस तरह के प्रयास और वह भी सरकार की नीयत और नीतियों से पोषित हों तो पूरे देश के लिये उसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन राहुल की चिताओं के साथ कुछ प्रश्न भी स्वत: ही खड़े हो जाते हैं। क्योंकि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिये मतदाताओं से ऐसे मुफ्ती के वायदे कर रहे हैं जिनमें से एक दो को भी पूरा करने के लिये पूरा बजट गड़बड़ा जाता है। मुफ्ती के वायदों को पूरा करने के लिये या तो जनता पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों का बोझ डालना पड़ता है या फिर कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। इस समय कांग्रेस केन्द्र में सत्ता में नहीं है। केवल तीन राज्यों में उसकी सरकारें हैं। ऐसे में यह देखना आवश्यक हो जाता है कि कांग्रेस की यह सरकारें राहुल के मानकों पर कितना खरा उतर रही हैं। क्योंकि कंपनी के एकाधिकार का विकल्प केवल सरकार होती है। जब कोई सरकार कोई भी सेवा प्रदान करने के लिये आउटसोर्स के नाम पर प्राइवेट कंपनी का रुख करती है तो एकाधिकार का सारा विरोध अर्थहीन हो जाता है। सरकारें अपने प्रतिबद्ध खर्चे कम करने के लिये सरकार में कर्मचारियों की भर्ती करने के स्थान पर आउटसोर्स का रास्ता अपना रही है। हर सेवा और उत्पादन में प्राइवेट सैक्टर का रुख किया जा रहा है। कर्ज सरकार के नाम पर और भरपाई जनता से सेवा प्रदान करने के नाम पर के चलन को जब तक नहीं रोका जायेगा तब तक यह एकाधिकार का विरोध केवल कागजी ही रहेगा। क्योंकि आज तो सरकारें कर्ज लेकर होटल का निर्माण करके उसे चलाने के लिए प्राइवेट सैक्टर के हवाले कर देती हैं। क्या प्राइवेट सैक्टर को स्वयं कर्ज लेकर स्वयं निर्माण करके होटल स्वयं नहीं चलना चाहिये? यही स्थिति शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हो रही है। सरकार एक तरह से बड़े सरमायेदार के एजैन्ट की भूमिका तक ही रह गयी है। राहुल गांधी को इस मुद्दे पर अपनी राज्य सरकारों को निर्देशित करके प्राइवेट सैक्टर के दखल को कम करने का प्रयास करना चाहिये।

सड़क पर विरोध प्रदर्शन इस्लामी न्यायशास्त्र और नैतिकता के खिलाफ

गौतम चौधरी

इस्लाम के पवित्र ग्रंथों की शिक्षाओं और न्यायशास्त्र में न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उत्पीड़न का विरोध किसी प्रकार किया जाए इसकी मुकम्मल हिदायत दी गयी गयी है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इन्हें सार्वजनिक व्यवस्था और शांति के मापदंडों के भीतर हर समय नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। इस्लाम ऐसे किसी भी कार्य पर रोक लगाता है जो हिंसा भड़काता है, या समाज में शांति को बिगाड़ता है, जिसमें से एक सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन भी शामिल है, जो दैनिक जीवन को परेशान कर सकता है और राज्य की व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। अल-राहुरि"याह, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसी तरह इस्लाम द्वारा बरकरार रखा गया है। यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है बल्कि इसे सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव और आम भलाई को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह एक प्रकार का धार्मिक अनुशासन है। कई इस्लामी विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि इस्लाम में संचार का इस्तेमाल लोगों के बीच नफरत, अमानवीयकरण या विभाजन को भड़काने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इरादा समाज में सद्भाव और समझ पैदा करना है। शूरा या परामर्श का विचार, मुसलमानों को अपने दृष्टिकोण को इस तरह से व्यक्त करने में सक्षम बनाकर मुक्त भाषण के मूल्य पर भी जोर देता है जो समग्र रूप से समुदाय के लिए फायदेमंद हो।

कई इस्लामिक विद्वान पवित्र ग्रंथों का हवाला देते हुए कहते हैं कि इस्लाम उत्पीड़न का विरोध करने का समर्थन करता है, लेकिन केवल तब तक जब तक यह सही के दायरे में रहता है। यहीं पर विरोध का मुद्दा उठता है। हालाँकि इस्लामी ढाँचा स्पष्ट रूप से विरोध प्रदर्शनों को गैरकानूनी नहीं ठहराता है, लेकिन यह उनके आचरण पर सख्त दिशानिर्देश लागू करता है। इस्लाम के पवित्र ग्रंथों में कई मौकों पर सीमाओं का उल्लंघनष् करने के खिलाफ चेतावनी दी गयी है। यह एक विशेष रूप से प्रासंगिक सबक है जब अनियंत्रित सार्वजनिक रैलियों के परिणामस्वरूप हिंसा, संपत्ति का विनाश या निर्दोष लोगों को नुकसान होता है। विरोध प्रदर्शन के दौरान अनियंत्रित भावनाएं खतरनाक साबित होती हैं। मीडिया की सुर्खियां आम तौर पर दर्शाती हैं कि विरोध प्रदर्शन अराजक हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ और नागरिकों को चोटें आई। कई बार तो हिंसक भीड़ को हत्या करते हुए तक देखा गया है। इन स्थितियों में, न्याय के नाम पर कार्य करना स्वीकार्य नहीं है और इस्लामी मूल्यों का उल्लंघन है। इस्लाम विवादों को सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक ढंग से सुलझाने की वकालत करता है।

बहराईच में हाल की सांप्रदायिक झड़पों को ध्यान से देखें तो थोड़ा अटपटा जरूर लगता है। इस्लाम न्याय की अवधारणाओं और किसी की राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, इन स्वतंत्रताओं का हमेशा जिम्मेदारी से पालन किया जाना चाहिए। इस्लाम का ढाँचा स्पष्ट है। यह ऐसे कृत्यों को रोकता है जो चोट पहुँचाते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, या हिंसा भड़काते हैं। ऐसे विरोध प्रदर्शन जो फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जैसे संपत्ति का विनाश या हिंसा के कार्य - इस्लाम के साथ असंगत हैं। इस्लामी मान्यताएं मुसलमानों को अहिंसक तरीकों से न्याय पाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जो विरोध के अधिकार पर एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य प्रदान करती हैं।

यदि अन्याय जारी रहता है, तो कानूनी उपचार के रूप में बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इस्लाम का संदेश- जो धार्मिक ग्रंथों के नैतिक उपदेशों पर आधारित है- निष्पक्षता, सद्भाव और जिम्मेदार अभिव्यक्ति पर आधारित है। आइए हम उस पवित्र ग्रंथों की शिक्षा को याद करें जो कहती है कि- जो कोई किसी निर्दोष की जान लेगा, यह ऐसा होगा जैसे उसने पूरी मानवता को मार डाला, और जो कोई किसी की जान बचाता है, यह ऐसा होगा मानो उसने सारी मानवता को बचा लिया हो।

डा. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना में एक प्रतिशत की ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण का प्रावधान

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणवत्ता के साथ ही उच्चतर शिक्षा तक प्रत्येक युवा की पहुंच भी सुनिश्चित कर रही है। इसी उद्देश्य से डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरम्भ की गई है, ताकि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कोई भी हिमाचली युवा उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहने पाए। योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को एक प्रतिशत की ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण का प्रावधान किया गया है।

योजना के तहत नए छात्रों के साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र भी इसका लाभ ले सकते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, पैरा-मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, विधि इत्यादि में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा बहुतकनीकी संस्थानों से तकनीकी पाठयक्रम तथा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों व विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के लिए मदद के उद्देश्य से यह योजना आरम्भ की गई है।

योजना का लाभ उठाने के लिए केवल हिमाचली बोनाफाइड युवा ही पात्र हैं। पात्र विद्यार्थी के पिछली कक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है और मेरिट के आधार पर ही प्रवेश होना चाहिए। विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित तहसील अथवा उपमंडल के कार्यकारी दण्डाधिकारी की ओर से जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आनलाईन अथवा पत्राचार माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

योजना के तहत भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यावसायिक अथवा तकनीकी पाठयक्रम या पीएचडी करने वाले छात्रों को रहने, ठहरने, शिक्षण शुल्क, पुस्तकों सहित शिक्षा से जुड़े अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। यह ऋणअर्द्ध वार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर विभिन्न किस्तों में प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक से यह ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस ऋण अनुदान की निरंतरता विद्यार्थी द्वारा संबंधित पाठयक्रम में संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्भर करेगी और इस बारे में संबंधित संस्थान के मुखिया अथवा विभागाध्यक्ष की ओर से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। विद्यार्थियों को यह प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष बैंक शाखा में जमा करवाना होगा। पाठयक्रम बीच में ही छोड़ देने की स्थिति में छात्र को पूर्व में प्राप्त किया गया ब्याज अनुदान वापस लौटाना होगा।

अपनी पसंद के संस्थान में प्रवेश से पूर्व संबंधित छात्र को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। साथ ही उसे वांछित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। पोर्टल के संचालन में आने तक विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र भरकर ई-मेल के माध्यम से भी दस्तावेज सहित आवेदन निदेशक उच्च शिक्षा को प्रेषित कर सकता है। उच्च शिक्षा निदेशक पात्रता के आधार पर बैंक को प्रथम किस्त जारी करने की संस्तुति 72 घंटों की अवधि में देंगे, ताकि प्रवेश शुल्क सहित अन्य निधि उन्हें प्रवेश के समय आसानी से उपलब्ध हो सके। साढ़े सात लाख रुपए तक के ऋण पर किसी भी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होगी। अंतिम अनुदान किस्त पाठयक्रम पूर्ण होने तक प्रदान की जाएगी। आवेदक छात्र के माता-पिता अथवा अभिभावकों को पात्रता से संबंधित शपथ पत्र भी देना होगा।

प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में उपायुक्तों के पास कॉर्पस फंड का भी प्रावधान किया गया है। बैंकों में किन्हीं कारणों से प्रथम किस्त जारी करने में देरी होने की स्थिति में उपायुक्त इस कॉर्पस फंड से पहली किस्त पात्र छात्रों को जारी करेंगे। आवेदन प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर यह राशि जारी की जा सकेगी, ताकि छात्र के प्रवेश को सुरक्षित किया जा सके।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि मंडी जिला में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग व बैंक प्रबंधन सहित सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध व त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस योजना का लाभ पात्र छात्रों को समय पर प्रदान किया जा सके। इस योजना से जरूरतमंद छात्रों का भविष्य संवरने के साथ ही उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के उनके सपने भी साकार हो रहे हैं।

शिक्षा के माध्यम से एक उज्जवल भविष्य का निर्माण

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024

हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं, जिससे हमारे देश के युवाओं को विदेश जाने की जरूरत न पड़े। हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों को लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं पड़े। इतना ही नहीं हम ऐसे संस्थान भी बनाना चाहते हैं जो विदेशों से लोगों को भारत आने के लिए आकर्षित करें। -नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और प्रमुख शिक्षाविद् मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के भविष्य को आकार देने में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। ऐसे में उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना काफी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार मजबूत शिक्षा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए समर्पित है जो छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देती है और युवाओं को राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने के लिए सशक्त बनाती है।

शिक्षा के माध्यम से भारत में बदलाव

भारत सरकार ने विभिन्न उपक्रमों और संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21-ए के माध्यम से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत को सुदृढ़ किया गया। यह छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक स्कूल में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हो। सरकारी योजनाओं और पहलों द्वारा समर्थित ये कानूनी ढांचे सभी के लिए एक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

एनईपी 2020 : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को मंजूरी दी। एनईपी 21वीं सदी की जरूरतों के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहती है, जिससे अधिक समावेशी और आगे की सोच वाले दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सके।

पीएम श्री : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 सितंबर 2022 को पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के घटकों को प्रदर्शित करते हुए पूरे भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को मजबूत करना है। यह योजना छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ज्ञान संबंधी विकास और 21वीं सदी के कौशल को बढ़ावा देगी। 27, 360 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ इसे पांच वर्षों (2022-2027) में लागू किया जाएगा। जिसमें 18,128 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में दिया जाएगा।

समग्र शिक्षा : एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ अनुरूप समग्र शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए एक समावेशी और न्यायसंगत कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि और जरूरतों को पूरा करता है। 1 अप्रैल 2021 को शुरू की गई यह योजना पांच साल तक जारी रहेगी। यह योजना 31 मार्च, 2026 को समाप्त होगी। यह विभिन्न छात्र समूहों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने और शैक्षणिक क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है।

प्रेरणा: 15 जनवरी, 2024 से 17 फरवरी, 2024 तक गुजरात के वडनगर के एक स्थानीय स्कूल में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया गया। यह पहल एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है जो कक्षा IX से XII तक के चयनित छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से विरासत को नवाचार के साथ मिश्रित करते हुए एक अनुभवात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण अनुभव प्रदान करना है। प्रत्येक सप्ताह देश भर से 20 छात्रों (10 लड़के और 10 लड़कियों) का एक बैच कार्यक्रम में भाग लेगा।

उल्लास : इसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम-एनआईएलपी) के रूप में भी जाना जाता है। उल्लास को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-2027 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। यह केंद्र प्रायोजित पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को सशक्त बनाना है, विशेष रूप से उन लोगों को जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य उनकी साक्षरता को बढ़ाना है, जिससे वे समाज में बेहतर ढंग से एकीकृत हो सकें और देश के विकास में सक्रिय रूप से योगदान कर सकें।

निपुण भारत : समझ के साथ पढ़ने और अंकगणित में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत) 5 जुलाई 2021 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू की गई थी। मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और अंकगणित में दक्षता प्राप्त करे। 2026-27 तक इसका लक्ष्य पूरा करना है।

विद्या प्रवेश : ग्रेड-I के बच्चों के लिए तीन महीने के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉडयूल के लिए विद्या प्रवेश दिशानिर्देश 29 जुलाई 2021 को जारी किए गए थे। इस पहल का उद्देश्य ग्रेड-I में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए एक गर्मजोशी भरा और स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करना, सहज परिवर्तन सुनिश्चित करना और सकारात्मक सीखने के अनुभव को बढ़ावा देना है।

विद्यांजलि: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 7 सितंबर 2021 को शुरू किए गए स्कूल स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। साथ ही देश भर में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल और निजी क्षेत्र से योगदान को प्रोत्साहित करके स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

दीक्षा: भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा 5 सितंबर 2017 को इसे शुरू किया गया था। इस मंच का उद्देश्य शिक्षा में नवीन समाधानों और प्रयोगों में तेजी लाकर शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को बढ़ाना है। दीक्षा राज्यों और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) को उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए मंच को रुचि के अनुसार लचीलेपन के साथ सशद्र बनाती है। इससे देश भर के शिक्षकों, शिक्षाविदों और वैसे छात्र जो आगे चलकर शिक्षक बनना चाहते हैं उनको लाभ होता है।

स्वयं प्लस: स्वयं प्लस, जिसे आधिकारिक तौर पर 27 फरवरी 2024 को माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया था। यह पहल उच्च शिक्षा में क्रांति लाने और उद्योग-प्रासंगिक पाठयक्रमों के लिए एक अभिनव क्रेडिट मान्यता प्रणाली को लागू करके कौशल विकास, रोजगार क्षमता और मजबूत उद्योग साझेदारी बनाने पर जोर देकर रोजगार क्षमता में सुधार करना चाहती है।

निष्ठा: 21 अगस्त 2019 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) का उद्देश्य 42 लाख प्राथमिक शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के व्यावसायिक विकास को बढ़ाना है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यक्रम को 6 अक्तूबर 2020 को निष्ठा-ऑनलाइन में परिवर्तित कर दिया गया, जिसे दीक्षा प्लैटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। इस सफलता को देखते हुए 2021-22 में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए निष्ठा 2.0 को शुरू किया गया था। वहीं, मूलभूत साक्षरता और अंकगणित पर ध्यान केंद्रित करते हुए 7 सितंबर 2021 को निष्ठा 3.0 पेश किया गया था।

एनआईआरएफ रैंकिंग: शिक्षा मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर 2015 को शुरू की गई राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) ने भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एनआईआरएफ ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के मूल्यांकन और रैंकिंग, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए एक संरचित और पारदर्शी प्रणाली शुरू की है।

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके मेधावी छात्रों का सहयोग करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। यह योजना भारत भर के शीर्ष 860 संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए शिक्षा ऋण प्रदान करती है, जिससे हर साल 22 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होते हैं। 2024-25 से 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ इस योजना का लक्ष्य अतिरिक्त 7 लाख छात्रों की सहायता करना है। पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और छात्र-केंद्रित प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित पीएम-विद्यालक्ष्मी देश भर के छात्रों के लिए आसान पहुंच और सुचारू अंतरसंचालनीयता (पारस्परिकता) सुनिश्चित करता है।

उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा में निवेश

वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत का मार्ग इसकी शिक्षा प्रणाली की ताकत से निकटता से जुड़ा हुआ है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने और एक सुदृढ़ शिक्षण वातावरण तैयार करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को रिकॉर्ड 73,498 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 12,024 करोड़ रुपये (19.56%) की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है, जो शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

विशेष रूप से प्रमुख स्वायत्त निकायों को अब तक का सबसे अधिक आवंटन किया गया है। इसमें केंद्रीय विद्यालयों (केवीएस) को 9,302 करोड़ रुपये और नवोदय विद्यालयों (एनवीएस) को 5,800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पर्याप्त निवेश भारत की शिक्षा प्रणाली को और ऊपर उठाने के स्पष्ट इरादे को रेखांकित करता है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उच्च शिक्षा विभाग का बजट आवंटन 47,619.77 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें 7,487.87 करोड़ रुपये योजनाओं के लिए और 40,131.90 करोड़ रुपये गैर-योजना व्यय के लिए समर्पित हैं। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3,525.15 करोड़ रुपये या 7.99% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। विशेष रूप से विशिष्ट योजनाओं के लिए आवंटन में 1,139.99 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो उच्च शिक्षा के भीतर लक्षित पहलों पर मजबूत ध्यान केंद्रित करता है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन में वृद्धि : एआईएसएचई रिपोर्ट 2021-22

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2021-2022 जारी किया। 2011 में अपनी स्थापना के बाद से एआईएसएचई देश भर के सभी पंजीकृत उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) से व्यापक डेटा एकत्र कर रहा है, जिसमें छात्र नामांकन, संकाय (फैकल्टी) और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख मापदंडों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण में पिछले कुछ वर्षों में हुए महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डाला गया है, जो भारत के शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति को दर्शाता है। इसमें नामांकन में बढ़ोतरी, समावेशिता में वृद्धि और मजबूत बुनियादी ढांचा शामिल है, जो एक अधिक मजबूत और गतिशील उच्च शिक्षा व्यवस्था में योगदान देता है

महिला नामांकन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 2014-15 में 1.57 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गई है। इसमें 32% की वृद्धि दर्ज की गई है। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों सहित वंचित समूहों के छात्रों के नामांकन में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें सभी श्रेणियों में महिला नामांकन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। 2021-22 में लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई) 1.01 तक पहुंच गया, जो पुरुषों की तुलना में उच्च शिक्षा में अधिक महिला छात्रों के नामांकन की निरंतर प्रवृत्ति को उजागर करता है।

अध्ययन के क्षेत्रों के संदर्भ में एसटीईएम विषयों में नामांकन में लगातार वृद्धि देखी गई है। 2021-22 में यूजी, पीजी और पीएचडी स्तरों पर 98.5 लाख छात्रों ने दाखिला लिया है। तमाम चुनौतियों के बावजूद महिलाएं चिकित्सा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला जैसे विषयों

में अग्रणी हैं। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर भी 2013-14 में 21% से घटकर 2021-22 में 13% हो गई है।

वित्त वर्ष 2024-25 में उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 3,525.15 करोड़ रुपये (7.99%) की बजट वृद्धि देखी जो उच्च शिक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने और समावेशी विकास का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

निष्कर्ष

शिक्षा बाधाओं को तोड़ने, अवसरों के द्वार खोलने और व्यक्तियों को समाज में सार्थक योगदान करने के लिए सशक्त बनाने की शक्ति रखती है। निरंतर नवाचार और व्यापक सुधारों के माध्यम से एक मजबूत प्रणाली का निर्माण करते हुए भारत का शैक्षिक परिदृश्य महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और शिक्षण विधियों को एकीकृत करने वाले समग्र 360-डिग्री दृष्टिकोण को अपनाकर भारत एक ऐसा वातावरण बना रहा है जहां युवा आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें देश के विकास के लिए प्रमुख संपत्ति में बदल सकते हैं।

जैसा कि हम मौलाना अबुल कलाम आजाद की विरासत का सम्मान करते हैं, आइए हम सभी के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी भविष्य की आधारशिला के रूप में शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित करें।

3000 अध्यापकों की बैचवाइज भर्ती की, तीन हजार की प्रक्रिया जारीः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के तहत भूरेश्वर महादेव मंदिर में शीश नवाया तथा मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने मंदिर परिसर में भगवान शिव की नई प्रतिमा का अनावरण किया और और वन वाटिका भूरेश्वर तथा क्वागधार हैलीपैड का भी लोकार्पण किया।

इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है और अनेक सुधारों के परिणामस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को राज्य सरकार वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर तथा वर्ष 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ल्वासा चौकी से चण्ड़ीगढ़ सड़क को चौड़ा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूरेश्वर महादेव क्षेत्र को इको टूरिज्म की दृष्टिगत से विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की आर्थिकी मजबूत होगी तथा क्षेत्र के लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव

ला रही है, जिसके सकारात्मक परिवर्तन सामने आ रहे है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 6000 अध्यापकों के पद स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि 3000 अध्यापकों को बैचवाइज नियुक्ति प्रदान कर दी गई है तथा 3000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार नए संस्थान खोलने की बजाए पहले से खोले गए संस्थानों में अधोसंरचना तथा स्टाफ प्रदान करने को प्राथमिकता दी रही है ताकि बच्चों को सरकारी स्कूलों में बेहतर एवं गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के मामले में देश भर में 21वें स्थान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हर क्षेत्र में सुधारात्मक कदम उठा रही है और इसमें आ रही बाधाओं को जन सहयोग से पार किया जा रहा है।

इस अवसर विधायक अजय सोलंकी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर, कांग्रेस नेता दयाल प्यारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थें।

राज्यपाल ने नशा उन्मूलन के लिए पंचायतों की भूमिका विषय पर राज्यस्तरीय कार्यशाला का किया शुभारंभ

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सहभागिता से देवभूमि से नशे की बुराई का समूल नाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि की सार्थकता को बनाए रखने के लिए सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित कर प्रदेश के भविष्य युवाओं को नशे की प्रवृति से बचाया जाएगा।

राज्यपाल ने राजभवन में पंचायती राज विभाग द्वारा नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों के सेवन से निपटने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की राज्य के स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति को प्रभावित करने वाले विषय के सार्थक समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि युवा समाज की अमूल्य निधि है और युवाओं से जुड़े मामलों को प्रभावी ढंग से सुलझाने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने कहा कि नशे की बुराई से निपटने में पंचायती राज संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और जनप्रतिनिधि के तौर पर वे लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों से जागरूक कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर पंचायतें संवेदनशील लोगों की पहचान कर उन्हें नशे की आदत लगने से पहले उन्हें सहायता प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों की नशे की आदत से मजबूर लोगों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने में स्थानीय सहायता समूहों, पुनर्वास कार्यक्रमों और परामर्श केंद्रों के विकास को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका रहती है।

राज्यपाल ने कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में नशे के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके कारण सामाजिक मूल्य नष्ट हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस नशे पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है, साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों को भी लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभानी चाहिए और प्रदेश सरकार को नशा निवारण केंद्र संचालित करने चाहिए।

उन्होंने कहा कि पंचायतें स्थानीय कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम कर लोगों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक निगरानी और सतर्कता समितियों की स्थापना से मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को निर्णायक और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने सदस्यों को जिम्मेदारी से कार्य करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि हम सहभागिता के साथ इस नशे की बुराई पर अंकुश लगा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरूद्ध हमारी सामूहिक लड़ाई को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने प्रत्येक प्रतिभागी से इस कार्यशाला से मिलने वाले ज्ञान और रणनीतियों को धरातल में उतारने के लिए कहा।

इस अवसर पर राज्यपाल ने राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया। उन्होंने मादक पदार्थों के सेवन से निपटने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया।

इसके उपरांत राज्यपाल ने राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि नशा युवाओं से उनके सपनों और लक्ष्यों को छीन रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीण भारत के संरक्षक हैं और लोग उनसे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि जन सहभागिता के साथ जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक जैसे प्रयास किए जाने चाहिए। युवा क्लब, मनोरंजन क्लब तथा खेलकूद जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। प्रदेश में नशे पर रोक लगाने के लिए पुलिस बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन इस बुराई के विरूद्ध सभी को आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने राज्यपाल तथा ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री का स्वागत किया। उन्होंने विभाग द्वारा नशे तथा मादक पदार्थों के सेवन से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान करने में पंचायत प्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस तथा प्रशासन अपने स्तर पर अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कारवाई कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में सार्थक परिणाम हासिल करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होती है, इस कार्यशाला में 150 पंचायत प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं तथा 40 मास्टर ट्रेनर हैं।

पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में 15982 महिला प्रतिनिधि हैं।

प्रदेश में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को किया जा रहा सुदृढ़ः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश के संवेदनशील राज्यों में शामिल हैं। इसके दृष्टिगत वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य में त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश में सम्पूर्ण प्रतिक्रिया प्रबंधन को अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अधीन किया जाएगा। इससे किसी भी आपातकालीन और आपदा की स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। इसके साथ आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए होमगार्ड को दो वर्ष की अवधि के लिए एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार एसडीआरएफ को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत कर रही है। आपातकालीन स्थितियों में जानमाल की क्षति में कमी लाने के लिए इस प्रणाली को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भूस्खलन, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है और राज्य सरकार इन घटनाओं में कमी लाने के दृष्टिगत कार्य कर रही है।

मंडी, कुल्लू और शिमला जिला में बादल फटने की घटनाओं के बाद 1 अगस्त, 2024 को मुख्यमंत्री ने एक बैठक आयोजित कर वरिष्ठ अधिकारियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं में अमूल्य जीवन बचाने और अन्य क्षति को कम करने के लिए एकीकृत तरीके से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जानमाल की भारी क्षति होती है और इससे लोगों की आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर करती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण पर्यटन क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और स्थानीय लोगों की आजीविका भी प्रभावित होती है। इन आपदाओं के कारण महत्वपूर्ण अधोसंरचना की क्षति होती है जिसे पुनः स्थापित करने में काफी समय लग जाता है और राज्य में विकास की गति भी प्रभावित होती है।

उन्होंने कहा कि कृषि योग्य भूमि में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की आर्थिकी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। प्रदेश में पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने, भूकम्परोधी अधोसंरचना निर्मित करने और लोगों को जागरूक करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राकृतिक आपदा प्रदेश के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न करती है। इससे पर्यावरण की भी क्षति होती है और लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियां बाधित होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के खतरों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीव्र, एकीकृत और सुदृढ़ प्रतिक्रिया प्रणली सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कदम उठा रही है।

एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों में स्वैच्छिक एचआईवी जांच में बढ़ौतरी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि समिति द्वारा एड्स जागरुकता एवं प्रदेश में एचआईवी के सक्रिय मामलों का पता लगाने के लिए समय-समय पर

जागरुकता कार्यक्रमों एवं जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश एड्स नियंत्रण समिति द्वारा 12 अगस्त से 12 अक्तूबर, 2024 तक दो माह का एकीकृत स्वास्थ्य अभियान एवं सघन जागरुकता अभियान चलाया गया। इसके अर्न्तगत दो माह के भीतर 3,63,674 लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता एवं संवेदनशील समुदाय को विभिन्न बीमारियों जैसे टीबी, हेपेटाइटिस-बी एवं सी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एचआईवी व यौन रोगों की जांच करना तथा इन सभी बीमारियों के प्रति लोगों को जागरुक करना था।

इस अभियान के दौरान 1472 गांवों में जागरूकता अभियान चलाया गया तथा 127394 ग्रामवासियों को एचआईवी विषय पर जानकारी दी गई।

अभियान के अन्तिम चरण में सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के दौरान 2 अक्तूबर को 3615 ग्राम पंचायतों में 217600 लोगों को एचआईवी तथा यौन रोगों के प्रति जागरूक रहने एवं एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर लगभग 1,50,000 प्रचार-प्रसार सामग्री भी वितरित की गई।

हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा चलाए गए इस अभियान में 200 आशा कार्यकर्ताओं ने 7,0342 घरों में जाकर लोगों को एचआईवी/एड्स एवं टीबी के बारे में जागरूक किया।

मुख्यमंत्री और केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने विद्युत और आवास मामलों पर किया विचार-विमर्श

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और केन्द्रीय ऊर्जा तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश से संबंधित ऊर्जा एवं आवास के विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की ऊर्जा नीति के अनुरूप रॉयल्टी का मामला उठाया। उन्होंने नीति की रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत विद्युत परियोजनाओं में पहले

12 वर्षों के लिए 12 प्रतिशत, इसके उपरांत 18 वर्षों के लिए 18 प्रतिशत तथा आगामी 10 वर्षों के लिए 30 प्रतिशत रॉयल्टी की अनिवार्यता की गई है।

उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां पहले से इस नीति का अनुसरण कर रही है और केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को भी इसकी अनुपालना करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड प्रदेश की ऊर्जा नीति की अनुपालना नहीं करती है तब इस स्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार 210 मेगावाट लुहरी चरण-1, 382 मेगावाट सुन्नी परियोजना और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना को अपने अधीन लेने के लिए तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इन परियोजनाओं पर हुए खर्च प्रतिपूर्ति एसजेवीएनएल को देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एसजेवीएनएल ने कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किए बिना इन परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को राज्य के जल संसाधनों पर उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

इस मामले पर केन्द्रीय मंत्री ने निगम के अधिकारियों को 15 जनवरी, 2025 तक अन्तिम प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने मंडी जिले की 110 मेगावाट शानन परियोजना का पंजाब से अधिग्रहण सुनिश्चित करने में केन्द्र सरकार की सहायता के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की लीज अवधि समाप्त हो गई है। उन्होंने केन्द्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को इस परियोजना का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शानन परियोजना का क्षेत्र कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा है इसलिए यह परियोजना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अधीन नहीं आती है।

इस मामले पर केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि वे इस अधिनियम की समीक्षा कर इसके अनुसार कारवाई करना सुनिश्चत करेंगे।

मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार को भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को नवम्बर, 1996 से अक्तूबर, 2011 तक की अवधि के लिए प्रदेश को बकाया 13066 मिलियन यूनिट बिजली एरियर जारी करने के निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के हिमाचल प्रदेश के हक में आये निर्णय के बावजूद प्रदेश को अभी तक संबंधित राज्यों के द्वारा उचित हिस्सा नहीं दिया है। केन्द्रीय मंत्री ने इस मामले के संदर्भ में आम सहमति बनाने के लिए सभी हितधारक राज्यों के साथ एक संयुक्त बैठक बुलाने का आश्वासन दिया।

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए और राज्य के लिए स्मार्ट मीट्रिंग और बिजली क्षति को कम करने पर बल दिया।

सुक्खू और मनोहर लाल ने केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वच्छ भारत पोषण, अमृत, शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र से उदार वित्तीय सहायता का आग्रह किया। केन्द्रीय मंत्री ने प्रदेश को केन्द्र सरकार से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दौरे के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार व्यक्त करते हुये मनोहर लाल के इस दौरे को सार्थक पहल बताया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में इस दौरे के सकारात्मक परिणाम आएंगे।

जल्द होगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का गठन:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा

है कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी में संगठन से जुड़े ऐसे कार्यकर्ताओं को पूरा अधिमान दिया जाएगा जो पिछले लंबे समय से पार्टी के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहें हैं और जो पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समय दे रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उनके व मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के आग्रह पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को चुस्त दुरुस्त करने व संगठन में नए लोगों को शामिल करने के लिए पीसीसी के साथ साथ सभी ब्लॉक व जिला कार्यकारिणी को भंग किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद नई कार्यकारिणी गठित कर दी जाएगी। नई कार्यकारिणी में वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ ऐसे युवाओ, महिलाओं को शामिल किया जाएगा जो पिछले लंबे समय से बगैर किसी पद के पार्टी की सेवा कर रहें है।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए नई कार्यकारिणी के गठन की आवश्यकता पिछले लंबे समय से महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि पार्टी को अभी से 2027 के विधानसभा चुनावों के लिये कमर कसनी होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जल्द ही एक बैठक कर संगठन का पूरा खाका तैयार किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा जांच दलों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सड़क सुरक्षा जांच दलों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपनी जांच दलों की क्षमता और कौशल को

बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, विशेषकर सड़क सुरक्षा प्रवर्तन के क्षेत्र में। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी), नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य के क्षेत्रीय जांच अधिकारियों के लिए सड़क सुरक्षा पर एक विशेष तीन दिवसीय प्रशिक्षण यातायात, पर्यटक और रेलवे (टीटीआर) इकाई, शिमला द्वारा आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण 5 से 7 नवंबर, 2024 तक डीजीपी हिमाचल प्रदेश, डॉ. अतुल वर्मा, आईपीएस के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता एआईजी टीटीआर, विनोद कुमार, एचपीएस ने की, जबकि पाठयक्रम का समन्वयन अतिरिक्त एसपी टीटीआर, नरवीर सिंह राठौर ने किया। इस कोर्स में सड़क दुर्घटनाओं की जांच और यातायात कानून प्रवर्तन के लिए आधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें एल्को सेंसर, डॉपलर रडार, और लेजर स्पीड मीटर जैसे उन्नत उपकरण शामिल थे। प्रशिक्षण के दौरान, विशेषज्ञ वक्ताओं और प्रशिक्षकों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहन जानकारी प्रदान की। एनआईसी शिमला में iRADके राज्य रोल-आउट प्रबंधक, अंकुश ठाकुर ने iRAD एप्लिकेशन के कार्यान्वयन पर एक प्रस्तुति दी, जो दुर्घटना मामलों की डिजिटल रिपोर्टिंग में सहायक है। इसके अलावा, इंजीनियर नरेश कुमार ने एल्को सेंसर और लेजर स्पीड मीटर का प्रदर्शन किया। डॉ.अमित शर्मा ने सड़क आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रमुख सत्रों का नेतृत्व अतिरिक्त एसपी नरवीर सिंह राठौर, एआईजी विनोद कुमार, एएसआई जगत सिंह और एएसआई संजीव कुमार ने किया, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों पर चर्चा की गई। प्रमुख प्रशिक्षण विषयों में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया, साइट निरीक्षण, दुर्घटना स्थल की फोटोग्राफी, साइट प्लान ड्राफ्टिंग (नक्शा मौका) और गवाह के ब्यान रिकॉर्डिंग शामिल थे। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये 35 जांच अधिकारियों, मुख्य रूप से जिला यातायात शाखाओं से, ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। यह कार्यक्रम उनके जांच कौशल को मजबूत करने के साथ-साथ उन्हें प्रभावी प्रवर्तन और सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस करने में सहायक सिद्ध हुआ।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश पुलिस की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें निरंतर व्यवसायिक विकास और आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग शामिल है।

उपायुक्तों को उपमंडल स्तर पर राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने डीसी-एसपी सम्मेलन के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों के अधिकारियों के साथ संवाद किया और उन्हें अपने-अपने जिलों में सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपायुक्तों को उपमंडल स्तर पर राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करने और 31 दिसंबर, 2024 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी डीसी और एसपी की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट एपीआर के लिए नए प्रदर्शन-आधारित नियम बनाए हैं। पिछली वर्णनात्मक ग्रेडिंग प्रणाली की तुलना में अधिकारी मूल्यांकन के लिए अब संख्यात्मक ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करने पर बल दिया। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विंग बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को एफसीए क्लीयरेंस मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को समय पर विकास परियोजनाओं का लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि एफसीए मामलों में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है।

उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अनाथ बच्चों को परामर्श प्रदान करें। उन्हें मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दें ताकि वे इसका पूरा लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि इच्छुक अनाथ बच्चों के लिए एक्सपोजर टूर को स्वीकृति देने की शक्तियां डीसी स्तर पर सौंपी जाएंगी ताकि उन्हें ऐसे एक्सपोजर विजिट करने में किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए उपायुक्तों को जिला मुख्यालयों पर गोशालाओं के निर्माण के लिए भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लावारिस पशु सड़कों पर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, वहीं किसानों के लिए भी चुनौतियां पैदा होती हैं।

उन्होंने जिला प्रशासन को इस समस्या को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को अपने जिलों में खाली पड़े सरकारी भवनों की पहचान करने और वर्तमान में किराये के भवनों में पर चल रहे सरकारी कार्यालयों को खाली पड़े भवनों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को अपने जिलों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कहा क्योंकि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हरित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन, जल विद्युत, डेटा भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों पर दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ ध्यान केंद्रित कर रही है। सम्मेलन के दौरान सात जिलों के डीसी और एसपी ने अपने-अपने जिलों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा, प्रशासनिक सचिव और विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने भी भाग लिया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

महाराष्ट्र में समोसे की राजनीति हो रही या विकास की:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुंबई में कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ने विकसित भारत सोच की आधारशिला रखी है। यह पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सोच है, जिन्होंने देशहित में नीतियाँ बनाई जिनके कारण आज भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा 'जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया। फिर मैंने पूछा कि यहां जो राजनीति हो रही है, वह समोसे पर है या विकास पर, महिलाओं के सम्मान पर? सच हमेशा झूठ का सामना करता है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। महाराष्ट्र की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान 'ऑपरेशन लोटस' चलाया गया।

सुक्खू ने कहा कि जब से भाजपा का ऑपरेशन लोट्स हिमाचल प्रदेश में फेल हुआ है, तब से प्रदेश को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ऑपरेशन लोट्स का युद्ध की तरह सामना किया। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई और फिर से कांग्रेस के विधायकों की संख्या फिर से चालीस हो गई है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध दुष्प्रचार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता को तय करना है, धनबल से कांग्रेस सरकारों को गिराने के षडयंत्र से क्या लोकतंत्र मज़बूत हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्ध राज्य बनाने के प्रयास कर रही है। इसके लिए नीतिगत बदलाव किया जा रहा ताकि विकास की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो साल से कम अवधि में पाँच गारंटियों को पूरा कर दिया है। पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की, पहली कक्षा से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ पर 27 वर्ष तक अनाथ बच्चों की देखभाल का दायित्व राज्य सरकार कर रही है, जिसके लिए एक कानून बनाया गया है। इसके साथ ही विधवा एवं एकल महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च भी राज्य सरकार उठा रही है। दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। कांग्रेस सरकार ने गाय के दूध का रेट 32 से बढ़ाकर 45 रूपये और भैंस के दूध का रेट 47 से बढ़ाकर 55 रूपये किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा जो कहती है, वह करती है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार गारंटियों से आगे बढ़कर काम कर रही है क्योंकि वंचित वर्ग की मदद करने का दायित्व भी राज्य सरकार का होता है।

हैरानी की बात है समोसो पर सरकार की जांच: सतपाल सत्ती

शिमला/शैल। भाजपा जिला शिमला की बैठक को संबोधित करते

हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आयी है, नित नए स्कैण्डल, नित नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, अलग-अलग तरह की जांचे हो रही है। उन्होनें कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का एक नया वाक्या मीडिया के माध्यम से सामने आया है जिससे पूरे देश में इस सरकार की किरकिरी हो रही है। मुख्यमंत्री के किसी कार्यक्रम के लिए शिमला के रैडिसन होटल से समोसे और अन्य खाने का सामान मंगाया गया और उसको स्टाफ के लोगो ने खा लिया और हैरानी की बात है कि इन समोसो पर सरकार ने जांच बिठा दी। सतपाल सत्ती ने बताया कि प्रदेश में बड़े-बड़े स्कैण्डल हो रहे हैं और मुख्यमंत्री को और पुलिस विभाग को यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रदेश में हो रहे बड़े-बड़े स्कैण्डलो में मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सचिवालय तक कौन-कौन, क्या-क्या खा रहा है, उसका ध्यान रखना चाहिए न कि छोटी-छोटी बातों में जाना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि इस समोसे प्रकरण की इन्क्वायरी बिठाना बहुत हैरान कर देने वाली बात है। सतपाल सत्ती ने कहा कि मेरा मानना है कि इस सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है बल्कि कार्यक्रम के अंदर मंगाये गये समोसों की इन्क्वायरी की चिंता है। यह सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और इस सरकार का पूरे देश के अंदर मजाक बन चुका है। हिमाचल प्रदेश जो अपनी सुंदरता और ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसको इस सरकार ने बदनाम करके रख दिया है और ऐसा लगता है कि यह सरकार अपने कृत्यों के कारण जल्द ही सत्ता से बाहर जाएगी।

क्या हर विधानसभा क्षेत्र में खुलेगा मुख्यमंत्री कार्यालय:रणधीर शर्मा

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख व श्री नैना देवी जी विधानसभा

क्षेत्र से विधायक रणधीर शर्मा ने जारी एक ब्यान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से पूछा कि क्या वे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यालय खोलेंगे? उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदय ने देहरा विधानसभा क्षेत्र जहां से उनकी पत्नी विधायक है, मुख्यमंत्री कार्यालय का उद्घाटन किया, इसलिए मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि क्या ऐसे मुख्यमंत्री कार्यालय हर विधानसभा में खुलेंगे या फिर यह कार्यालय सिर्फ पत्नी के विधानसभा क्षेत्र में ही खुलना है।

रणधीर शर्मा ने कहा कि एक तरफ प्रदेश की कमजोर आर्थिक स्थिति का बहाना बना कर पिछ्ली भाजपा सरकार द्वारा खोले गए 1500 संस्थान बन्द कर दिए और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के विधानसभा क्षेत्र में नित नये संस्थान खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहावत तो थी कि 'सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ' परन्तु मुझे लगता है व्यवस्था परिवर्तन का नारा दे कर बने मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस कहावत को भी बदल दिया और यह सिद्ध कर दिया की 'सारा प्रदेश एक तरफ और उनकी पत्नी का विधानसभा क्षेत्र एक तरफ।'

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी को 4 महीने चुनाव जीते हुये नहीं है और 5 नवंबर को पति मुख्यमंत्री ने देहरा में एसपी कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय का शुभारंभ भी कर दिया साथ ही एचआरटीसी कर्मशाला, जलशक्ति विभाग अधीक्षण अभियंता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग अधीक्षण अभियंता कार्यालय, बिजली बोर्ड अधीक्षण अभियंता कार्यालय और खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय भी खोल दिए। एक तरह मुख्यमंत्री प्रदेश भर में कार्यालय बंद कर रहे है जिसमें उनके कांग्रेस के नेता द्वारा प्रस्तावित कार्यालय भी बंद कर दिए गए जिससे उन्हीं के कांग्रेसी विधायक विरोधाभास की राजनीति के शिकार हो गये। यह विधायक मुख्यमंत्री के पत्नीमोह से परेशान हो कर अपने ही सीएम से नाराज़ एवं रुष्ठ हो गए है।

हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री महोदय की इस पक्षपात पूर्ण और विरोधाभासी राजनीति की कड़ी निन्दा करती है।